CPI(M)

जन जोहार झारखण्ड

अंक–10 मासिक बुलेटिन मार्च 2023

संपादकीय ....

विस्थापित जनता को उजाड़े जाने के खिलाफ अब याचना नहीं रण होगा

झारखंड के कई जिलों में कथित अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर रैयतों और मेहनतकशों को उजाड़े जाने के काम में तेजी आ गई है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की खनन कंपनियां, रेलवे, इस्पात उधोग के अधिकारी सभी रैयतों, किसानों और वर्षों से रह रहे मेहनतकशों को अतिक्रमणकारी कह कर उन्हें बलपूर्वक हटाने के काम में जुट गए हैं। कोल इंडिया की झारखंड स्थित कोल कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग की कुख्यात एजेंसियों को इस काम में लगाया गया है। जिन्हें झारखंड सरकार का जिला प्रशासन और पुलिस की मदद भी हासिल हो गयी है। जिसके चलते कई स्थानों पर बसे हुए गरीबों को उजाड़ने और उन्हें आर्तकित करने के लिए बल प्रयोग कर और झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इससे कई जगह तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है और लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

हमारी स्पष्ट समझ है कि झारखंड में हम औधोगिक गतिविधियों के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि यह एक खनिज बहुलता वाला राज्य है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड का एक बड़ा भौगोलिक हिस्सा संविधान की 5 वीं अनुसूची, आदिवासियों और दूसरे गरीबों के जमीन संबधी अधिकारों का रक्षा कवच छोटानागपुर, संताल परगना काश्तकारी कानूनों, पंचायतों के लिए विशेष पेसा अधिनियम और सर्वोपरि ग्रामसभा की सहमति सबंधी विशेष अधिकारों के दायरे में आता है। इन अधिकारों का उल्लंघन भारत के संविधान की अवमानना है।

लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक की सभी सरकार ने झारखंड के आदिवासियों और दूसरे गरीबों को संविधान द्वारा दिए गये उपरोक्त अधिकारों का लगातार उल्लंघन ही किया है। आजादी के बाद यहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए रैयतों और किसानों ने इसलिए अपनी जमीन दी कि उधोग धंधे

..... शेष पेज 3 पर

लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल विछाओ–कामगारों का पलायन रोको

झारखंड में लोहा, कोयला, बिजली उत्पादन और वितरण जैसे बड़े उद्योगों को लगातार कॉरपोरेट्स के हवाले किया रहा है। झारखंड में व्यापक पैमाने पर उपलब्ध खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के बाबजूद यहां रोजगार उपलब्ध नहीं है। सरकारी खजाना राजकोष से भरा पड़ा है, फिर भी मानव विकास के हर सूचकांक में झारखंड निचले पायदान पर क्यों है?

झारखंड को टाटा, अडानी, मेदांता, जिंदल, बिरला, मित्तल जैसे पूंजीपतियों का चारागाह बना दिया है। बड़े उद्योग और खनन पूर्णतरू कॉरपोरेट्स के कब्जे है। लेकिन झारखंड में छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों का व्यापक विकास क्यों नहीं किया गया? जो थोड़े बहुत हैं भी, उसे बड़े पूंजीपतियों से बचाने के लिए कोई नीति और कार्यक्रम नहीं बनाया गया। इसी कारण से झारखंड के मेहनतकश झारखंड से बहुत ही अल्प मजदूरी, दूसरे अर्थों में कहे तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम की तलाश में हर वर्ष छह से आठ महीना दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है।

खनिज और वन संपदा से भरपूर झारखंड में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की अपार संभावना रही है, जो व्यापक तौर पर झारखंड के लोगों को काम और रोजगार का अवसर दे सकती है और जिससे झारखंड के कामगारों का दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में वार्षिक पलायन रोका जा सकता है। क्या झारखंड के पास इतनी क्षमता नहीं है कि लघु और कुटीर उद्योगों का राज्य भर में जाल बिछाया जा सके? इन उद्योगों की स्थापना में न तो भारी पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी और न ही लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित करना पड़ेगा।

झारखंड में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए रांची, जमशेदपुर, बोकारो और संथाल परगना में क्रमशः रांची औद्योगिक विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक विकास प्राधिकार और संथाल परगना औद्योगिक विकास प्राधिकार पहले ही मौजूद है। राज्य सरकार को बताना चाहिए इन संस्थाओं की मदद से कितना लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया गया और बजट में कितनी राशि आवंटित की गई थी। इसी तरह से झारखंड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम एवं

..... शेष पेज 3 पर

ईसीएल प्रबंधन और गोड्डा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन

ईसीएल प्रबंधन और गोड्डा जिला प्रशासन राजमहल कोल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले मे अराजक भूमिका अदा कर रहा है। झारखंड राज्य किसान सभा और आदिवासी अधिकार मंच द्वारा गठित भूमि संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित रैयतों की एक विरोध सभा को संबोधित करते हुए माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि तालझारी मौजा समेत कई जगह रैयत और किसान आक्रोशित हैं लेकिन जिला प्रशासन रैयतों को और ग्रामीण महिलाओं को अपमानित कर मामले को और उलझा रहा है और इतना ही नहीं उनपर बल प्रयोग भी कर रहा है। ईसीएल का दावा है कि उसने तालझारी मौजा मे 125 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है। लेकिन इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई क्योंकि यहां के अधिकांश रैयतों का कहना है कि उन्हें अधिग्रहण से संबंधित कोई नोटिस ही नहीं मिला है। ईसीएल, जो अब स्वयं आऊट सोर्सिंग पर निर्भर है, रैयतों से सीधे बातचीत भी नहीं कर रहा है और आउटसोर्सिंग कंपनी मां अंबे जिला प्रशासन का इस्तेमाल कर रैयतों पर हमले कर रही है, उनपर झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें डराने के काम मे लगी हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि यह सरकार एक ओर अडाणी जैसे धन पशुओं को, जो हमारी वित्तीय संस्थानों को खोखला कर रहे हैं, को संरक्षण प्रदान कर रही है तो दूसरी ओर देश की राष्ट्रीय संपत्ति की लूट का एजेंडा आगे बढा रही है। इस बार का बजट इसका सीधा प्रमाण है कि किस तरह, मनरेगा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मद मे बजट को घटा दिया गया है और बड़े पूंजीपतियों को टैक्स मे भारी छुट दे दी गई है।

सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के उपाध्यक्ष एहतेशाम अहमद ने कहा कि इस इलाके के सांसद और विधायक चाहे वे किसी भी दल के हों रैयतों के पक्ष मे कुछ नहीं बोल रहें हैं।

आज की इस सभा को बाधित करने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन की आलोचना की। सभा को किसान नेता और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक साह, आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष सुभाष हेम्ब्रम आदि ने भी संबोधित किया। □

माकपा का राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर

पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित रुप से आने वाले दिनों मे आंदोलन एवं संगठन का नेतृत्व करने और उनकी राजनीतिक चेतना व सांगठनिक दक्षता को विकसित किए जाने के उद्देश्य से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की झारखंड राज्य कमिटी द्वारा जामताड़ा में 4 और 5 फरवरी को राज्यस्तरीय दो दिवसीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

माकपा का राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर रांची में

माकपा का दो दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 18 एवं 19 मार्च को एसडीसी हॉल, रांची में आयोजित है। इस शिविर में राज्य स्तर के शिक्षकों का बुनियादी मार्क्सवाद, पार्टी संविधान, पार्टी कार्यक्रम और कार्यनीतिक लाईन पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में नीचे ब्रांच स्तर तक के लिए लगातार पार्टी शिक्षा पर कार्यक्रम तय किया जाएगा।

इस शिक्षण शिविर में बुनियादी मार्क्सवाद, भारतीय दर्शन की प्रगतिशील परंपरा और पार्टी व जनसंगठन तथा संतालपरगना व छोटानागपुर काश्तकारी कानून जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। शिक्षक के रूप मे जाने–माने मार्क्सवादी चिंतक बादल सरोज, पार्टी के पूर्व केंद्रीय कमिटी सदस्य और मेहनतकशों की हिंदी पत्रिका सीटू मजदूर तथा अंग्रेजी पत्रिका ''द वर्किंग क्लास'' के कार्यकारी संपादक ज्ञान शंकर मजुमदार ने इस शिक्षा शिविर में राज्य भर से आए 80 नेतृत्वकारी साथियों के समक्ष उपरोक्त विषयों पर विस्तार से बातें रखीं।

शिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए सीपीआई (एम) झारखंड के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने पार्टी शिक्षा की जरूरत के बारे में अपनी बातें रखी और सबसे तन्मयता से भागीदारी का आह्वान किया।

प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक बादल सरोज ने समृद्ध भारतीय दर्शन की प्रगतिशील परंपरा के बारे में विस्तार से अपनी बातें रखी और वामपंथ को इसका असली वारिस बताया। CNT और SPT एक्ट पर बोलते हुए ज्ञान शंकर मजुमदार ने इन दोनों कानूनों को झारखंड की असल पहचान बता कर इनकी हर हाल में रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने जनसंगठनों के कार्य प्रणाली पर भी विस्तार से बातें रखी और उन्हें चुस्त दुरुस्त रखते हुए श्रमिक वर्ग के अगुआ के रूप में स्थापित करने का भी आह्वान किया।

सफल आयोजन के लिए जामताड़ा जिला कमिटी को बधाई दी गई। □

अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन

झारखंड में अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत वे लगातार भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। उनकी राज्य सरकार से मांग है कि आपकी सरकार के आश्वासन के अनुसार 2014 के नियमावली के तहत अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के सेवाओं को नियमित करने की दिशा में तत्काल उचित कदम उठाया जाए।

सीपीआई(एम) के झारखण्ड राज्य सचिव द्वारा इस मुद्दे पर हेमन्त सरकार को पत्र लिखा गया कि वे अपने स्तर से हस्तक्षेप करते हुए सकरात्मक रूख अपनाते हुए कर्मचारी हित को देखते हुए इसे खत्म करने की दिशा में पहल करें। क्योंकि इन पैरा मेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर भी असर पड़ रहा है। □

झारखण्ड राज्य किसान सभा एवं सीटू का संयुक्त प्रमण्डलवार कन्वेंशन

झारखंड राज्य किसान सभा द्वारा धनबाद, रांची, पलामू और दुमका में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा प्रमंडलीय स्तर पर कन्वेंशन आयोजित किए गए। जिसे मुख्य वक्ता के रूप में कॉ0 कृष्णा प्रसाद, कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अवधेश कुमार ने संबोधित किया। उपरोक्त वक्ताओं ने कहा कि एम.एस.पी. के लिए कानून बनाने एवं तीन कृषि कानून के खिलाफ 13 माह चली किसान आन्दोलन में 715 किसानों की शहादत के पश्चात मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करते हुए तीन माह में एम.एस.पी. के लिए कानून बनाने के लिखित आश्वासन के साल भर बाद भी एम.एस.पी. का कानून नहीं बनाया और मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। केन्द्र सरकार द्वारा लगातार किसान – मजदूर विरोधी नीतियों को थोपने, खेत, खेती कारपोरेट के हवाले करने, बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के खिलाफ 5 अप्रैल को दिल्ली कूच का आव्हान किया गया।

दिल्ली चलो आह्वान के तहत सीटू ने भी चासनाला और अन्य जगहों पर मजदूरों का कन्वेंशन किया। □

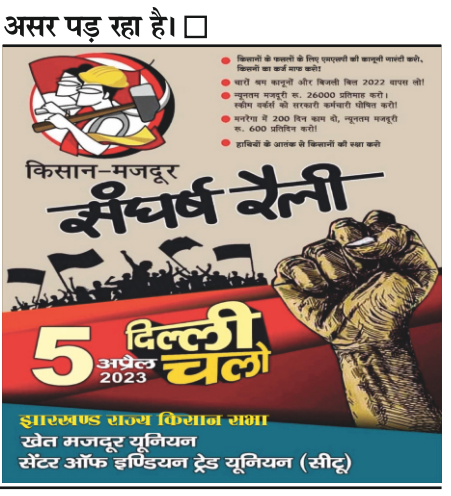

धनबाद प्रमण्डल

रांची प्रमण्डल

दुमका प्रमण्डल

चासनाला

पलामू प्रमण्डल

खूंटी

यूएपीए और देशद्रोह कानून को रद्द करने के लिए हस्ताक्षर अभियान

तय कार्यक्रम के अनुसार 25 और 26 फरवरी को रांची शहर के 6 प्रमुख स्थलों पर फादर स्टैन स्वामी के जेल में हुई हत्या के दोषियों को सजा एवं देशभर के जेलों में बंद मनवाधिकार–राजनीतिक कार्यकर्ताओं, निर्दोष गरीबों और आदिवासियो की जेलों से रिहाई और UAPA और देशद्रोह के कानून को रद्द करने की मांग को ले कर आज शहीद फादर स्टैन स्वामी न्याय मोर्चा के वैनर तले विभिन्न वाम और जनवादी संगठनों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कैम्पेन में 20 हजार से अधिक रांची के प्रबुद्ध नागरिकों छात्रों, युवा, महिलाओं और पुलिसकर्मियों ने अपना हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान सरकार और न्यायायिक कुव्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा साफ दिखा। अभियान के माध्यम से हस्ताक्षर युक्त प्रतियां महामहिम राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। बगईचा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता फादर टोनी ने कहा कि फादर स्टैन समेत हजारों निर्दोष गरीबों के न्याय के लिए यह दूसरे दौर का आभियान है जो पूरे राज्य भर में चलेगा।

उन्होंने कहा कि आर्सेनल कंसलटेंसी के खुलासे के बावजूद केंद्र सरकार की इस विषय पर चुप्पी समझ से परे है। □

सम्पादकीय .....

..... शेष पृष्ठ 1 का

स्थापित होने से उन्हें और उनकी नौजवान पीढी को रोजगार मिलेगा और औधोगिक विकास से खुशहाली आएगी। लेकिन जिनकी जमीन गई उनमें से प्रथम चरण के विस्थापित 15 लाख रैयतों को न तो मुआवजा मिला न ही उनका पुनर्वास हुआ और न ही रोजगार मिला। ऐसे रैयत अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

सीपीआई (एम) विस्थापन की समस्या को झारखंड के चहुंमुखी विकास के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखता है क्योंकि झारखंड के रैयतों और किसानों का अनुभव यह प्रमाणित करता है जबतक उनके पुनर्वास और रोजगार के लंबित मामलों का निपटारा एक समय सीमा के अंदर नहीं होता है तबतक वे खनन सहित नए उधोग – धंधों के प्रति सशंकित रहेंगे। इसी पृष्ठभूमि में सीपीआई (एम) ने यह तय किया है कि राज्य में विस्थापितों व विस्थापन की समस्या को लेकर जो भी संगठन आंदोलन कर रहे हैं उन्हें एक मंच पर लाने, विस्थापन की विभिन्न समस्याओं का ठोस अध्ययन करने और एक समन्वय समिति बनाकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। □

कामगारों का .....

..... शेष पृष्ठ 1 का

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम की भी भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए कि इन क्षेत्रों में उनके प्रयास से कितने लघु एवं कुटीर उद्योग लगे और कितने लोगों को रोजगार मिला? इस मद में बजट में आवंटित राशि क्या पर्याप्त थी ? अगर पर्याप्त नहीं है तो और कितनी राशि आवंटित की जानी चाहिए थी? और अगर पर्याप्त है, तो बजट की कुल राशि क्यों नहीं खर्च की जाती है?

कार्यकाल के साढ़े तीन सालों में मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। मौजूदा सरकार नौकरी के नाम पर ज्यादा डायलॉग बाजी करती रही कि हम इतने हजार लोगों को शिक्षक की, पुलिस की और अन्य तृतीय और चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में नौकरी देंगे। पर हुआ कुछ नहीं, लाखों रिक्तियों को अबतक नहीं भरा गया। यह सरकार 1932 खतियान का माला जपते–जपते अपने कार्यकाल का तीन वर्ष पूरा कर चुकी है, पर अबतक नियोजन नीति बनाने में असफल रही। अगर बनाने का प्रयास भी किया तो असंवैधानिक और गैरकानूनी नियोजन नीति को पेश किया, जिसका खामियाजा रिक्तियों की भर्ती की आस में लगे बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है।

हर मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की यह सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह बेरोजगारों से खेल रही है। सरकार जानबूझकर असंवैधानिक और गैरकानूनी नीतियां बनाती है, ताकि मामला उच्च न्यायालय में फंस जाय, जिससे सारी रिक्तियों पर भर्ती रुक जाए। असल में यह सरकार काम करना नहीं चाहती है, बल्कि काम करते हुए दिखाना ज्यादा चाहती है।

अब समय आ गया है भाजपा–आजसू, झामुमो–कांग्रेस के इतर विकल्प की, जो विभाजनकारी और कॉरपोरेट्स परस्त नीतियों को खारिज कर जनता के असली मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। ''भाजपा हटाओ, झामुमो लाओ'' या ''झामुमो लाओ, भाजपा हटाओ'' जैसे सरकार बदली कार्यक्रमों से यथास्थितिवाद ही कायम रहेगा, राज्य की बेहतरी के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए वामपंथ के नेतृत्व में संगठित आंदोलनों द्वारा ही राज्य सरकार पर लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाकर व्यापक रोजगार सृजन के लिए दबाव बनाया जा सकता है। □

– मनोहर लाल मुंडा

रांची

बोडाम

राहे

जमशेदपुर

पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 00170200000219
IFSC Code : BARB0RANCHI

सोती सरकार – अक्रामक गजराज

पहाड़ों के वैध–अवैध उत्खनन, लगातार चलते क्रशर, जंगलों सुरक्षा बलों की तैनाती ने जंगली जानवरों को अपना ठिकाना बदलने को बाध्य कर दिया है। झारखंड के जंगलों में रहने वाले जानवर अब गांवों में पहुंच रहे हैं। गांवों की व्यवस्था से अनजान इन जानवरों को भी जंगल से बाहर आते ही कम संकट नहीं झेलना पड़ रहा है। सिर्फ बिजली के करंट से तकरीबन 20 हाथियों की मौत झारखंड में हो चुकी है। पिछले दो साल में झारखंड में जंगली हाथियों ने जंगल से बाहर आकर हमला किया जिस में 200 से अधिक लोग मारे गये। साल 2020–21 में 74 और 2021–22 में 133 लोगों को हाथियों ने मार डाला। ये सिलसिला 2022–23 में भी जारी है. हाथी जब जंगलों से बाहर आते हैं तो जान–माल दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं।

झारखंड वन और पहाड़ों का राज्य है और जंगली जानवरों की आश्रयस्थली है। पहाड़ों पर वैध–अवैध उत्खनन के लिए विस्फोटक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, रात–दिन क्रशर चलते रहते हैं, जो जंगली जानवरों की शांति में खलल डालता है। अबतक करीब दो दर्जन पहाड़ उत्खनन के कारण खत्म हो चुके हैं। पहाड़ की जगह अब समतल जमीन हो गयी है जिस वजह से पहाड़ों से निकलने वाली नदियां सूखने के कगार पर हैं। सुरक्षा बलों की जंगलों में गतिविधियां भी इनके चौन में खलल डालती हैं। जंगलों की बेतरतीब कटाई भी इनके आश्रय के लिए बड़ी समस्या है। यही वजह है कि गुस्से में जानवर अब जंगल छोड़ गांवों की ओर आ रहे हैं। भालू, तेंदुआ और हाथी के हमले झारखंड के लिए अब ये नयी बात नहीं हैं। ये हाथियों का उत्पात नहीं है, उनका आक्रोश है, जो उन्हें उग्र बना रहा है।

मुनाफे के लिए अंधे हो कर जंगल के पर्यावरण को उजाड़ा जा रहा है। सरकारों के संज्ञान में सब कुछ है और अवैध उत्खनन उसकी नाक के नीचे भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार चल रहा है। □

तस्वीरों में कार्यक्रम ...

इस्पात मजदूर मोर्चा बोकारो

AIKS द्वारा तोरपा प्रखण्ड का घेराव

कोयलानगर धनबाद

बजट के खिलाफ तमाड़ लोकल कमिटी का धरना

बजट को लेकर धनबाद लोकल कमिटी की रैली

महेशपुर लोकल कमिटी द्वारा अंचल कार्यालय पर धरना

सीटू, किसान सभा एवं खेतिहार मजदूर यूनियन का कोल्हान स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन आयोजित

धनबाद

सिन्दरी

पार्टी शिक्षण कार्यक्रम – जामताड़ा

रांची

विश्व सामाजिक न्याय दिवस – कांके रांची

राजभवन के समक्ष संयुक्त धरना

बोकारो

गोमिया

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव प्रकाश विप्लव द्वारा संपादित एवं प्रेषित। संयोजन बिपिन कु0 सिन्हा।
माकपा पार्टी कार्यालय : विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, वेबसाईट : cpimjharkhand.org, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com